

वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति ढलान पर है जिसकी शुरुआत 2018 की प्रथम तिमाही में व्यापार तनावों, बढ़ी हुए वित्तीय संवेदनशीलता, भू-राजनैतिक जोखिमों व संबंधित अनिश्चितताओं बुरी तरह प्रभावित परिवेश में हुई। वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद वैश्विक विनियामक सुधारों के कार्यान्वयन से बैंकों की पूँजी व चलनिधि बफर्स में वृद्धि हुई। अशोध्य ऋण को कम करने और तुलनपत्र को मजबूत करने के उनके प्रयासों को कम वृद्धि व कम ब्याज दरों के परिवेश ने बाधा पहुँचाई है। विश्व भर में, नीति निर्माता विनियामक ढाँचे को सुदृढ़ बना रहे हैं और बैंकों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक लागू कर रहे हैं। इन नीतियों का तत्काल कोई परिणाम न दिखे, परंतु वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता व पुनरुत्थानशीलता के बढ़ने से मध्यावधि व दीर्घावधि में इनका फायदा मिलना चाहिए।

## 1. परिचय

11.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति ढलान पर है जिसकी शुरुआत व्यापार तनावों, बढ़ी हुए वित्तीय संवेदनशीलता, भू-राजनैतिक जोखिमों व संबंधित नीतिगत अनिश्चितताओं से बुरी तरह प्रभावित परिवेश में 2018 की प्रथम तिमाही में हुई। विश्व-भर में और सभी विकसित व उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में समान रूप से, मंदी का सामना करने व इसे और गहराने से रोकने के लिए मौद्रिक नीति को उदार किया गया है। उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश का उपयोग माँग को अवलंब देने के लिए किया जा रहा है, लेकिन यह साफ़ दिख रहा है कि नीतिगत गुंजाइश या तो सीमित है या समाप्त।

11.2 ऋण के ऊँचे व बढ़ते जा रहे स्तरों जैसी वित्तीय कमजोरियों की अधिकता के चलते जोखिम विमुखता के फैलने व माँग के कमज़ोर होने के कारण 2018 के उत्तरार्ध से सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं व ईएमई में वित्तेतर क्षेत्र को जाने वाले बैंक-उधार में कमी आई है। यद्यपि बैंक और वित्तीय

संस्थाएं अच्छी तरह से पूँजीकृत रहे, उनकी लाभअर्जकता मौन पड़ी रही।

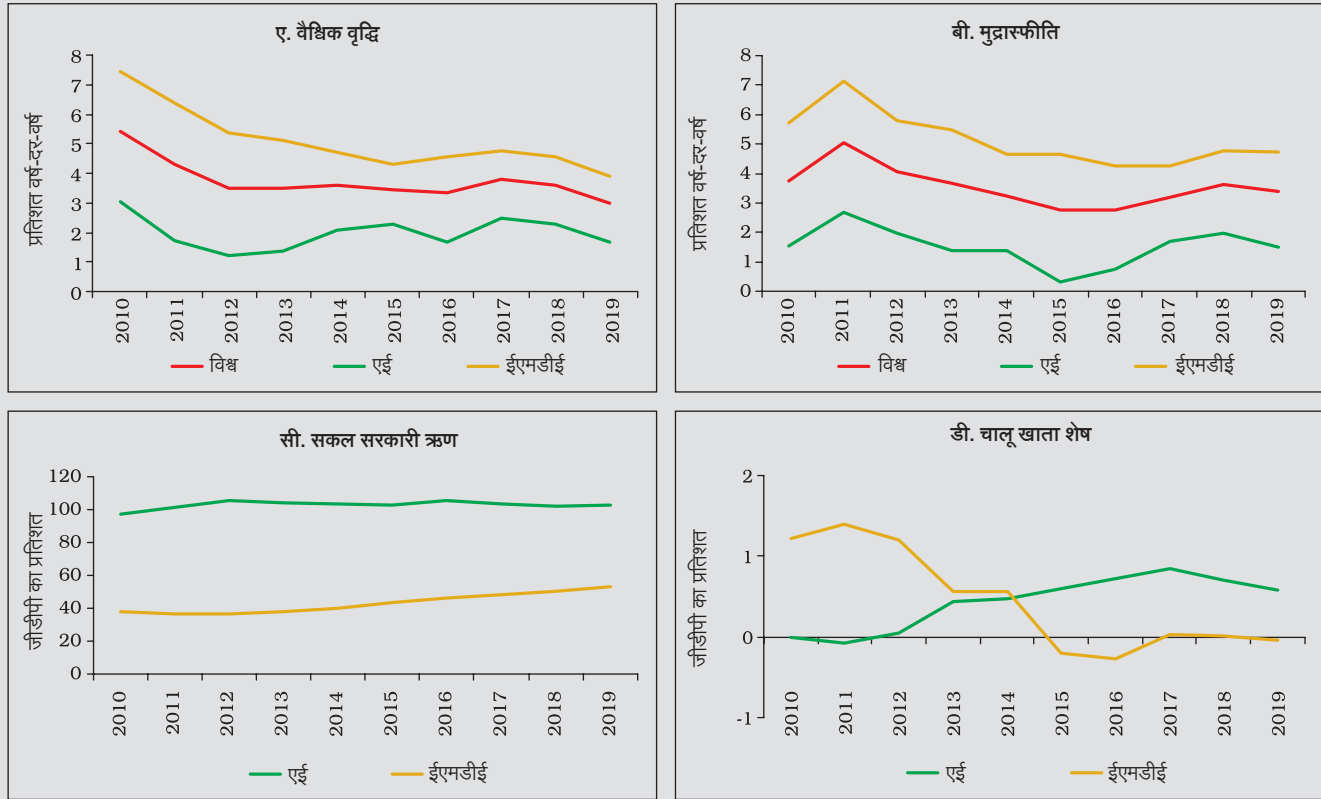
11.3 इस पृष्ठभूमि में खंड 2 उस समष्टि वित्तीय विन्यास की समीक्षा कर रहा है जिसमें वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था इन कठिन चुनौतियों का सामना कर रही है। वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था के प्रदर्शन का विश्लेषण खंड 3 में है जिसके बाद खंड 4 विश्व के सबसे बड़े 100 बैंकों के प्रदर्शन पर केंद्रित है। वैश्विक नीतिगत सुधारों के एजेंडे पर हुई प्रगति की चर्चा खंड 5 में है। खंड 6 इस अध्याय का सारांश देता है।

## 2. समष्टि-वित्तीय परिदृश्य

11.4 यद्यपि वैश्विक अर्थव्यवस्था के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से में वृद्धि में सुस्ती समान रूप से व्याप्त है, पर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह अधिक उजागर है<sup>1</sup> (चार्ट 11.1ए)। प्रणालीगत अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक कमजोरियों, प्राकृतिक आपदाओं और देश विशेष के कारकों ने बढ़ती शिथिलता को और गंभीर कर दिया है। ईएमई में पूँजी प्रवाहों में बढ़ी हुई अस्थिरता, विनिमय (एक्सचेंज) दरों और आस्ति कीमतों ने

<sup>1</sup> अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2019), 'ट्रांसस्क्रिप्ट ऑफ़ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवाज़ ओपेनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2019 वार्षिक बैठक, 17 अक्टूबर <https://www.imf.org/en/News/Articles/17/10/2019/tr-101719transcript-managing-director-kristalina-georgieva-press-conference-2019-annual-meetings>. पर उपलब्ध।

चार्ट II.1 समष्टि परिदृश्य



टिप्पणी : वर्ष 2019 का डेटा आईएमएफ का अनुमान है।  
 स्रोत : वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटा बेस।

समष्टि-आर्थिक संभावनाओं को क्षति पहुँचाई है और उनमें से कुछ में वैश्विक प्रभाव देश विशेष के कारकों के साथ मिल गए हैं जैसे असंवहनीय समष्टि-संतुलन, सरकारी ऋण के उच्च स्तर और पण्य कीमतों में कमजोरी के बावजूद मुद्रा के मूल्य-हास से उपजे मुद्रास्फीतीय दबाव (चार्ट II.1बी, सी और डी)।

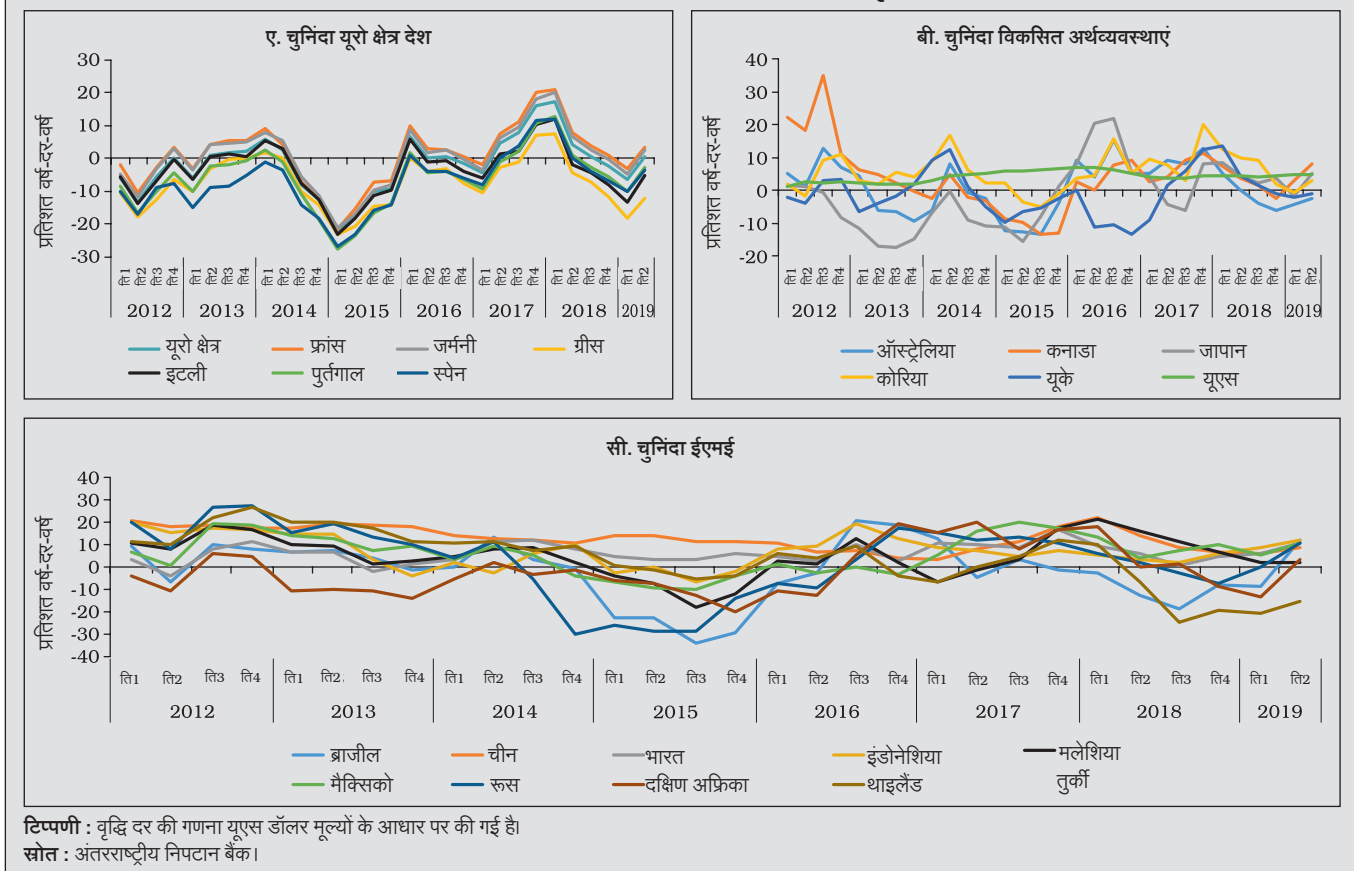
II.5 इन बातों को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2019 के लिए अपने पूर्वानुमान को अक्टूबर 2019 में घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया जो कि वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद अब तक की सबसे धीमी गति है।<sup>2</sup> विश्व व्यापार संगठन ने भी 2019 के लिए विश्व पण्य वस्तु व्यापार के संबंध में पहले के अपने 2.6 प्रतिशत के पूर्वानुमान को घटाकर 1.2 प्रतिशत कर दिया।<sup>3</sup>

II.6 यद्यपि 2018 की दूसरी छमाही में और 2019 की पहली तिमाही में बैंक ऋणों में नरमी आयी, 2019 की दूसरी तिमाही में कुछ बहाली आयी। हालांकि, देश विशेष के कारकों के अनुसार इसकी गति अलग-अलग रही है जैसे वित्तीय स्थितियां और बैंकों के तुलनपत्रों की सुदृढ़ता। कुछ एई, विशेषतः यूएस में चक्राभिमुखी राजकोषीय विस्तार, उदार मौद्रिक नीति और सहायक वित्तीय परिस्थितियों ने ऋण विस्तार को अवलंब प्रदान किया। इसके विपरीत, यूरो क्षेत्र में माँग में कमी और बैंकिंग क्षेत्र की कमजोरियों के कारण ऋण वृद्धि फीकी रही। यूरो क्षेत्र के बैंकों का सरकारी बाँण्डों में बड़ा एक्सपोजर एक प्रमुख जोखिम बना रहा, यद्यपि इसके भीतर एक देश से दूसरे देश में स्पष्टतः काफ़ी विविधता देखी गई। (चार्ट II.2)।

<sup>2</sup> अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2019), 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक - ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग डाउनटर्न, राइजिंग ट्रेड बैरियर्स', अक्टूबर।

<sup>3</sup> विश्व व्यापार संगठन (2019): 'ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एंड आउटलुक', 1 अक्टूबर, [https://www.wto.org/english/news\\_e/pres19\\_e/pr840\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/pres19_e/pr840_e.htm) पर उपलब्ध।

चार्ट II.2 निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र को बैंक ऋण में वृद्धि



11.7 ईएमई वाले देशों में, साफ़ तौर पर व्यापक विभिन्नताएं हैं जैसे एक छोर पर ब्राजील जैसे देश में सहायता प्राप्त ऋण (सब्सिडाइज़्ड क्रेडिट) के स्तर को कम करने (डिलीवरेजिंग), अधिक अंतरमध्यस्थता मार्जिनों और कमजोर माँग के कारण ऋण में कमी देखने को मिल रही है। कुछ दूसरे ईएमई जैसे रूस व भारत में, ऋण में चूक के बोझ से ऋण वृद्धि प्रभावित हुई, जबकि चीन में नीतिगत कदमों द्वारा पुनर्संतुलन, विनियामक कसाव और डिलीवरेजिंग के प्रयास बाधक का कार्य कर रहे हैं।

### 3. वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

11.8 बासेल III मानदंडों को लागू करने में सभी देशों में अलबत्ता अलग-अलग गति से प्रगति हुई। इस संदर्भ में, लाभप्रदता, आस्ति की गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और लीवरेज को मापने वाले संकेतकों के मुख्य समूह की समीक्षा उप- खंड में की गयी है।

### 3.1 आस्तियों पर प्रतिलाभ

11.9 समग्र तौर पर यूरो क्षेत्र और जापान की तुलना में अमेरिकी बैंकों ने कम लाभप्रदता के माहौल में काफी बेहतर प्रदर्शन किया। यूरो क्षेत्र में, बैंक की लाभप्रदता, कमजोर वृद्धि और उच्च एनपीएल से प्रभावित थी, हालांकि पुर्तगाल और स्पेन जैसी आस-पास की अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षाकृत कम ऋण हानि प्रावधानीकरण के कारण ऋण की वसूली धीमी रही। तथापि इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो कुछ देशों में मौजूद कम लागत-दक्षता, सीमित राजस्व विविधीकरण और कुछ क्षेत्रों में पुरानी आस्तियों का अधिक बन जाना जैसी संरचनात्मक कमजोरियां पूर्ण पुनरुद्धार में बाधा बनी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बैंकों ने अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाएं के समकक्ष बैंकों की तुलना में बेहतर लाभप्रदता बनाए रखी।

II.10 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय बैंकों की लाभप्रदता नगण्य रही, हालांकि, हालिया समय में सुधार का संकेत मिला है। आस्ति गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों, कर्जभार कम करना, ऋण वृद्धि में गिरावट तथा छोटे और मध्यम आकार के बैंकों के कमजोर तुलन पत्र के कारण चीन के बैंकों की लाभप्रदता पर भी 2018 में दबाव उत्पन्न हुआ। वर्ष 2019 में अब तक चीन के बैंकों में मजबूती दर्शायी है क्योंकि वे पुनः लाभ अर्जन की स्थिति में जा रहे हैं। प्रावधानीकरण में कमी आने से भी इसमें सहारा मिला और बड़े बैंकों ने अग्रणी भूमिका निभाई। उच्च ऋण चूक के बावजूद रूसी बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ, क्योंकि अनर्जक ऋण (एनपीएल)

के लिए अच्छी तरह से प्रावधान किए गए थे, और शुद्ध ब्याज आय और शुल्क तथा कमीशन आय दोनों में वृद्धि हुई थी। उच्च ब्याज मार्जिन और मजबूत ऋण वृद्धि के बल पर इंडोनेशिया के बैंक उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक लाभदायक साबित हुए। मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में बैंकों ने मजबूत आरओए (सारणी II.1) दर्ज किया।

### 3.2 पूंजी पर्याप्तता

II.11 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के लिए अतिरिक्त पूंजीगत बफ़र्स सहित, बासेल III मानदंडों के

सारणी II.1: आस्तियों पर प्रतिलाभ ( प्रतिशत)

	उन्नत अर्थव्यवस्थाएं									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019:ति1	2019:ति2
ऑस्ट्रेलिया	1.19	1.18	1.38	1.20	1.42	0.78	1.15	1.33	0.87	-
कनाडा	1.13	1.11	1.10	1.11	1.04	1.02	1.11	1.15	1.03	1.07
फ्रांस	0.39	0.31	0.49	0.23	0.40	0.40	0.42	0.42	0.31	0.38
ग्रीस	-9.52	-1.79	1.44	-0.97	-2.55	0.09	-0.17	-0.04	0.18	0.30
जर्मनी	0.53	0.45	0.36	0.37	0.40	0.37	0.37	0.32	-	-
इटली	-0.87	-0.06	-0.77	-0.20	0.26	-0.53	0.61	0.46	-	0.30
जापान	0.33	0.27	0.39	0.40	0.37	0.34	0.33	0.30	0.09	-
पुर्तगाल	-0.38	-0.33	-0.76	-1.34	0.16	-0.59	0.31	0.66	0.98	0.84
स्पेन	0.09	-1.39	0.38	0.43	0.48	0.39	0.52	0.61	0.62	0.57
यूके	0.29	0.17	0.22	0.33	0.28	0.25	0.49	0.50	-	-
यूएस	0.28	0.33	0.38	0.33	0.36	0.37	0.34	0.39	0.41	0.42
	उभरती अर्थव्यवस्थाएं									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019:ति1	2019:ति2
ब्राज़ील	1.73	1.41	1.38	1.35	1.49	1.12	1.47	1.58	1.66	1.73
चीन, पी.आर.: मेनलैंड	1.28	1.28	1.27	1.23	1.10	0.98	0.92	0.90	1.02	1.00
भारत	0.89	0.95	0.74	0.67	0.45	0.37	0.33	-0.01	-0.18	0.43
इंडोनेशिया	2.89	3.10	3.05	2.74	2.25	2.12	2.41	2.51	2.56	2.50
मलेशिया	1.51	1.58	1.49	1.49	1.24	1.35	1.44	1.42	1.35	1.51
मेक्सिको	1.54	1.83	2.08	1.66	1.63	1.69	2.05	2.20	2.41	2.26
फिलीपींस	1.60	1.81	1.88	1.57	1.38	1.35	1.34	1.32	1.40	1.49
रूसी परिसंघ	2.47	2.39	1.87	0.95	0.23	1.20	1.01	1.59	-	-
दक्षिण अफ्रीका	1.54	1.52	1.45	1.43	1.51	1.71	1.70	1.68	1.64	1.60
तुर्की	2.23	2.35	2.02	1.69	1.48	1.89	2.04	1.78	1.53	1.44

टिप्पणी : 1. – उपलब्ध नहीं है।

2. दिसंबर –अंत से संबंधित डेटा। जापान का डेटा सितंबर-अंत से संबंधित।

3. गहरा लाल रंग सबसे कम आरओए को दर्शाता है जबकि गहरा हरा रंग 2010-2019 के दौरान देश विशेष के सबसे ज्यादा आरओए का परिचायक है।

स्रोत : वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ।

कार्यान्वयन के कारण प्रमुख एई बैंकों में पूंजी की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। हालांकि, ग्रीस और इटली जैसे देशों में, अनर्जक ऋण में बढ़ोतरी के कारण पूंजी की स्थिति में हो रहा सुधार थम गया।

11.12 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों ने पूंजीगत बफ़र्स बनाने में कामयाबी हासिल की, जिसमें इंडोनेशियाई बैंकों का सीआरएआर उच्चतम रहा। चीनी बैंकों ने विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के बैंकों ने अपनी पूंजी की स्थिति को मजबूत किया। हालाँकि दबावग्रस्त आस्तियां उच्च स्तर

पर थीं, 2018 के दौरान रूसी बैंकों की पूंजी की स्थिति में सुधार हुआ लेकिन अन्य प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्था की तुलना में कम था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार द्वारा पूंजी अंतर्वेशन और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी उगाही के प्रयासों के कारण भारत में बैंकों की सीआरएआर में सुधार हुआ (सारणी 11.2)।

### 3.3 आस्ति गुणवत्ता

11.13 मुख्य रूप से संस्थागत और सरकारी हस्तक्षेप से कर्जभार कम करने की प्रक्रिया जारी रहने के कारण यूरो-क्षेत्र के आसपास की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में अनर्जक ऋण

सारणी 11.2: जोखिम भारत आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (प्रतिशत)

	उन्नत अर्थव्यवस्थाएं									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019:ति1	2019:ति2
ऑस्ट्रेलिया	11.6	11.9	11.6	12.2	13.8	13.6	14.5	14.8	14.7	-
कनाडा	15.9	16.2	14.3	14.2	14.2	14.8	14.8	15.2	15.2	15.2
फ्रांस	12.3	14.5	15.4	16.3	17.1	17.8	18.9	18.7	18.9	19
जर्मनी	16.4	17.9	19.2	18	18.3	18.8	19.4	18.9	18.7	18.8
ग्रीस	10.3*	9.6	13.5	14.1	16.5	16.9	17	16	15.6	16.5
इटली	12.7	13.4	13.7	14.3	14.8	13.8	16.7	16.1	-	16.5
जापान	14.2	14.2	15.9	15.3	15.9	16.2	16.7	17	17.2	-
पुर्तगाल	9.8	12.6	13.3	12.3	13.3	12.3	15.1	15.2	16	16.1
स्पेन	12.1	11.6	13.3	13.7	14.7	14.8	15.6	15.6	15.4	15.6
यूके	15.7	17.1	19.6	17.3	19.6	20.8	20.5	21.4	-	-
यूएस	14.7	14.5	14.4	14.4	14.1	14.2	14.5	14.8	14.9	14.9
	उभरती अर्थव्यवस्थाएं									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019:ति1	2019:ति2
ब्राजील	16.3	16.4	16.1	16.7	16.4	17.2	18.1	18	17.8	18
चीन, पी.आर.: मेनलैंड	12.7	13.3	12.2	13.2	13.5	13.3	13.6	14.2	14.2	14.1
भारत	14.2	14.2	13.9	13	13	13.3	13.7	13.8	14.3	14.1
इंडोनेशिया	16.1	17.3	19.8	18.7	21.3	22.7	23	22.9	23.3	22.5
मलेशिया	17.7	17.6	14.6	15.4	16.3	16.5	17.1	17.4	18	17.4
मेक्सिको	15.7	15.9	15.6	15.8	15	14.9	15.6	15.9	16	15.7
फिलीपींस	17.1	17.8	17	16.1	15.3	14.5	14.4	14.9	15.2	15.3
रूसी परिसंघ	14.7	13.7	13.5	12.5	12.7	13.1	12.1	12.2	-	-
दक्षिण अफ्रीका	15.1	15.9	15.6	14.8	14.2	15.9	16.3	16.1	16.3	16.8
तुर्की	16.6	17.9	15.3	16.3	15.6	15.6	16.8	17.3	16.4	17.7

टिप्पणी : 1. - : उपलब्ध नहीं है।

2. दिसंबर-अंत से संबंधित डेटा। जापान का डेटा सितंबर-अंत से संबंधित है।

3. # : डेटा सितंबर अंत से संबंधित है।

4. भारत का डेटा मार्च अंत से संबंधित है तथा भारतीय पर्यवेक्षी विवरणियों के आधार पर है।

5. गहरा लाल रंग सबसे कम सीआरएआर को दर्शाता है जबकि गहरा हरा रंग 2010-2019 के दौरान देश विशेष के सबसे ज्यादा सीआरएआर का परिचायक है।

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ तथा पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

<sup>4</sup> अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2019), 'ग्लोबल फिनांशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अप्रैल।

(एनपीएल) घट गए। आस्ति की बिक्री तथा राइट ऑफ के बावजूद यूरोप में ग्रीक बैंकों के क्षतिग्रस्त ऋणों का अनुपात सबसे अधिक रहा। कम-ब्याज दर और कम विकास के माहौल में लाभ की तलाश पूरे यूरो क्षेत्र में बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों की होल्डिंग बढ़ाने के लिए मजबूर कर रही है, हालांकि इससे ऋण बही में कुछ हद तक प्रतिकूल चयन की भी संभावना हो सकती है। फ्रांस और जर्मनी जैसी यूरो क्षेत्र की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एनपीए अनुपात गिरावट के रुझान के साथ काफी निचले स्तर पर बना रहा।

11.14 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता मिश्रित रही जिसमें ब्राजील और भारत ने सुधार दर्शाया परंतु रूस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की में स्थिति खराब रही।

नाजुक आर्थिक स्थितियों और प्रतिबंधों के कारण विशेष रूप से रूसी बैंकों के एनपीएल अनुपात में और अधिक गिरावट आयी। वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण दक्षिण अफ्रीका और तुर्की के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में भी गिरावट आयी। भारत में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों का विपरीत प्रभाव पड़ता रहा। हालांकि, क्षतिग्रस्त आस्तियों के समाधान और तुलन पत्र को सुधारने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में धीमी गति से ही सही, परंतु प्रगति हुई है और इसके प्रभाव से स्थिरता आ रही है (सारणी 11.3)।

### 3.4 लीवरेज अनुपात

11.15 लीवरेज अनुपात, जिसे पर्यवेक्षी टीयर 1 पूंजी और कुल जोखिम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता

सारणी 11.3: अनर्जक ऋणों का अनुपात (प्रतिशत में)

उन्नत अर्थव्यवस्थाएं										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019:ति1	2019:ति2
ऑस्ट्रेलिया	2	1.7	1.4	1	0.9	1	0.9	0.9	1	-
कनाडा	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	-	-	-
फ्रांस	4.3	4.3	4.5	4.2	4	3.6	3.1	2.7	2.7	2.6
जर्मनी	3	2.9	2.7	2.3	2	1.7	1.5	1.2	-	-
ग्रीस	14.4	23.3	31.9	33.8	36.6	36.3	45.6	42	42.2	40.3
इटली	11.7	13.7	16.5	18	18.1	17.1	14.4	8.4	-	8.1
जापान	2.4	2.4	2.1	1.7	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1	-
पुर्तगाल	7.5	9.7	10.6	11.9	17.5	17.2	13.3	9.4	8.9	8.3
स्पेन	6	7.5	9.4	8.5	6.2	5.6	4.5	3.7	3.6	3.4
यूके	4	3.6	3.1	1.7	1	0.9	0.7	1.1	-	-
यूएस	3.8	3.3	2.5	1.9	1.5	1.3	1.1	0.9	0.9	0.9
उभरती अर्थव्यवस्थाएं										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019:ति1	2019:ति2
ब्राजील	3.5	3.4	2.9	2.9	3.3	3.9	3.6	3.1	3.1	3.1
चीन, पी.आर.: मेनलैंड	1	1	1	1.2	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8
भारत	2.7	3.4	4	4.3	5.9	9.2	10	9.5	8.9	9.2
इंडोनेशिया	2.1	1.8	1.7	2.1	2.4	2.9	2.6	2.3	2.4	2.4
मलेशिया	2.7	2	1.8	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6
मेक्सिको	2.1	2.4	3.2	3	2.5	2.1	2.1	2.1	2	2.1
फिलीपींस	2.6	2.2	2.4	2	1.9	1.7	1.6	1.7	2	2
रूसी परिसंघ	6.6	6	6	6.7	8.3	9.4	10	10.1	-	-
दक्षिण अफ्रीका	4.7	4	3.6	3.2	3.1	2.9	2.8	3.7	3.8	3.7
तुर्की	2.6	2.7	2.6	2.7	3	3.1	2.8	3.7	3.8	4.1

टिप्पणी : 1. - : उपलब्ध नहीं है।

2. दिसंबर-अंत से संबंधित डेटा। जापान का डेटा सितंबर-अंत से संबंधित है। चीन का 2017 का डेटा जून-अंत से संबंधित है। इटली और यूके का 2018 का डेटा जून-अंत से संबंधित है। यूएस और रूसी परिसंघ रूस का 2018 का डेटा सितंबर-अंत से संबंधित है।

3. गहरा लाल रंग सबसे ज्यादा एनपीएल अनुपात को दर्शाता है जबकि गहरा हरा रंग 2010-2019 के दौरान देश विशेष के सबसे कम एनपीएल अनुपात का परिचायक है।

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ तथा पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

है, का लक्ष्य जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं में निहित प्रचक्रियता के विपरित कार्य करना है। बासेल III मानदंडों के अनुसार न्यूनतम 3 प्रतिशत लीवरेज अनुपात रखना अपेक्षित है। 2010 से बासेल III नियामक अपेक्षाओं के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लीवरेज अनुपात में सामान्यतः सुधार हुआ है। मेक्सिको और फिलीपींस जैसे देशों में बैंकों के लीवरेज अनुपात में मामूली वृद्धि से इन देशों में न्यूनतम लीवरेज अनुपात के कार्यान्वयन का पता चलता है (सारणी II.4)।

### 3.5 वित्तीय बाजार संकेतक

II.16 अमेरिकी बैंकों से संबंधित शेयर सूचकांकों में वर्ष 2018 के दौरान लगभग 18.3 प्रतिशत की गिरावट आयी जिसके बाद 2019 में (9 दिसंबर तक) 2.4 प्रतिशत की तेज बहाली हुई। यूएस के बैंकों की स्टॉक कीमतों में अस्थिरता आंशिक रूप से व्यापारिक तनावों, अल्पकालिक अवरोधों और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में व्याप्त अनिश्चितता से उत्पन्न उतार-चढ़ावों की भी द्योतक है।<sup>4</sup> यूरोक्षेत्र में नकारात्मक ब्याज दरों, आर्थिक संवृद्धि के प्रति निराशा का दृष्टिकोण, अनेक संरचनात्मक मुद्दों और राजनीतिक अनिश्चितता ने बैंक स्टॉक सूचकांकों पर

सारणी II.4: लीवरेज अनुपात (प्रतिशत में)

	उन्नत अर्थव्यवस्थाएं									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019:ति1	2019:ति2
ऑस्ट्रेलिया	5.3	5.1	5.1	5.2	6	6.6	6.9	6.9	6.8	-
कनाडा	4.9	4.9	5	4.9	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3
फ्रांस	4.8	5.2	5.8	5.3	5.8	5.9	6.6	6.5	6.3	6.2
जर्मनी	4.4	4.7	5.5	5.6	5.9	6	6.3	6.5	6.3	6.2
ग्रीस	5.7*	5.8	7.5	8.1	10	10.7	12	10.7	10.5	11
इटली	5.4	5.4	5.4	5.9	6.2	5.5	6.6	6.3	-	6.5
जापान	-	-	5.6	5.5	5.6	5.5	5.4	5.5	5.4	-
पुर्तगाल	5.1	6.7	6.8	6.4	7.2	6.5	7.7	7	7.5	7.4
स्पेन	5.9	5.8	6.8	7.2	7.4	7.8	7.6	7.6	7.5	7.5
यूके	5.1	5.5	6.3	5.6	6.8	7	6.8	6.8	-	-
यूएस	12.2	12	11.8	11.7	11.7	11.6	11.7	11.7	11.8	11.9
	उभरती अर्थव्यवस्थाएं									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019:ति1	2019:ति2
ब्राजील	10.1	10.1	9.3	9	8.5	9.3	10	10.1	10.2	10.3
चीन,										
पी.आर.:मैनलैंड	-	-	-	7.2	8.4	8.1	8.6	9.1	9	8.9
भारत	6.7	7	6.9	7.1	7.2	7.2	7.4	7.5	7.5	-
इंडोनेशिया	11	12.2	12.5	12.8	13.6	14.4	15.2	15.1	15.5	15.2
मलेशिया	8.9	9.4	9.6	10	10.5	11	11.2	11.2	11.4	11.6
मेक्सिको	9.9	10.6	10.4	10.8	10.4	9.9	10.4	10.7	11.1	10.7
फिलीपींस	11.1	11.7	9.7	9.9	10	9.7	10	10.7	11	11.1
रूसी परिसंघ	11.8	11.8	11.5	8.5	8.9	10.4	10.5	10	-	-
दक्षिण अफ्रीका	7.2	7.8	7.9	7.6	7	8.2	8.8	8.4	8.3	8.4
तुर्की	11.7	12.1	10.9	11.6	11	10.7	10.7	10.8	10.4	11.3

टिप्पणी : 1. - : उपलब्ध नहीं है।

2. दिसंबर-अंत से संबंधित डेटा। जापान का डेटा सितंबर-अंत से संबंधित है।

3. # : डेटा सितंबर-अंत से संबंधित है।

4. गहरा लाल रंग सबसे कम लीवरेज अनुपात को दर्शाता है जबकि गहरा हरा रंग 2010-2019 के दौरान देश विशेष के सबसे अधिक लीवरेज अनुपात का परिचायक है।

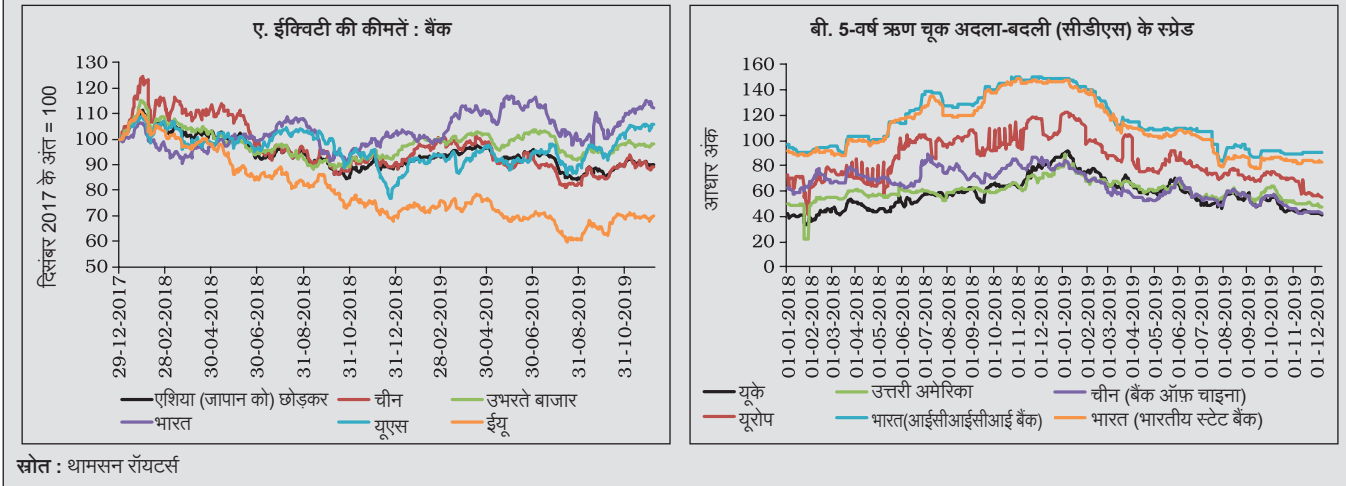
5. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2019), 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट', अक्टूबर

स्रोत : वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ।

<sup>4</sup> अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2019), 'ग्लोबल फिनांशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अक्टूबर।



चार्ट II. 3 : बैंकों की सेहत के बाजार-आधारित संकेतक



नकारात्मक प्रभाव डाला है और वे 2017 की समाप्ति के अपने स्तर से 30 प्रतिशत नीचे आ गए हैं। ईएमई में रहे खराब बैंकिंग कामकाज के कारण बैंक शेयरों पर प्रतिलाभ कम हो गया। पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा की गयी बिकवालियों के चलते भी कीमतें नीचे रहीं (चार्ट II.3ए)।

II.17 ऋण चूक अदला-बदली (सीडीएस) के बढ़ने से इस बात के संकेत मिलते हैं कि बैंक कथित तौर पर ऋण शोधन और पुनर्विन्तीयन में सक्षम हैं। कम और अधिक स्थिर सीडीएस स्प्रेड वाले बैंक जोखिम प्रीमिया का कम भुगतान करते हैं, जिसका लाभ यह होता है कि वे अपने ग्राहकों को सस्ती और आसान दरों पर वित्त प्रदान कर पाते हैं। बैंकों के सीडीएस प्रसार में 2018 की दूसरी छमाही में वृद्धि हुई थी, परंतु उसके बाद उसमें गिरावट आयी है। सबसे कम सीडीएस प्रसार यूके और उत्तरी अमेरिका में स्थित बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए थे। हाल के महीनों में, बैंक ऑफ चाइना का सीडीएस प्रसार ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिकी बैंकों के लगभग बराबर पहुंच गया। यूरो क्षेत्र के बैंकों का सीडीएस प्रसार सरकारी साख निर्धारण में आयी कमी और खराब ऋण गुणवत्ता के कारण अमेरिका और ब्रिटेन के बैंकों की तुलना में अधिक रहा। यूरो क्षेत्र में विद्यमान राजनीतिक अनिश्चितता का सीडीएस प्रसार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा क्योंकि आस-पास की कई अर्थव्यवस्थाओं में सरकारों और वित्तीय क्षेत्र के बीच घातक गठजोड़ काम कर रहा था (चार्ट II.3बी)।

#### 4. दुनिया के सबसे बड़े बैंक<sup>5</sup>

II.18 टीयर 1 पूंजी की दृष्टि से की गयी रैंकिंग के आधार पर एई और ईएमई में 2017 और 2018 के दौरान शीर्ष 100 बैंकों की श्रेणी में शामिल बैंकों की संख्या समान बनी रही (चार्ट II.4ए)। वर्ष 2018 में ईएमई के बैंकों की आस्तियों की हिस्सेदारी में हुई वृद्धि का प्रमुख श्रेय चीन को जाता है जिसके 18 बैंक शीर्ष 100 सूची में शामिल थे। अमेरिका ने स्वीडन के बिना पर शीर्ष 100 बैंकों में अपना हिस्सा बढ़ाया (चार्ट II.4बी)। हालांकि, एई और ईएमई के शीर्ष 100 बैंकों की कुल आस्तियों में वर्ष 2018 में एक साल पहले की तुलना में मामूली गिरावट देखी गयी। जर्मनी, यूके, जापान और ब्राजील में से प्रत्येक में एक-एक बैंक की आस्ति में 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गयी।

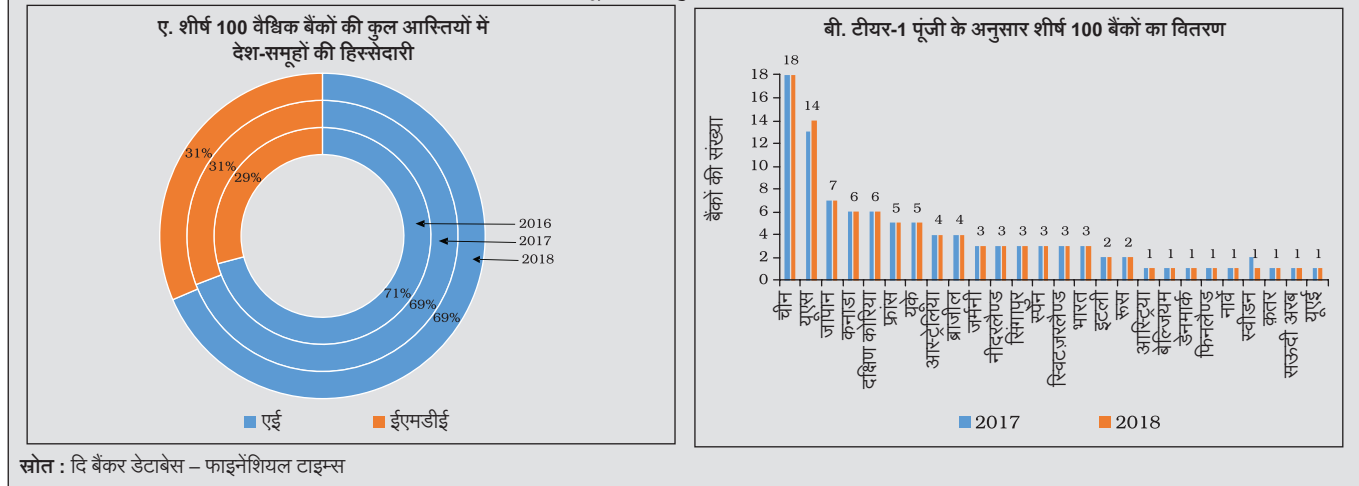
II.19 निवल ब्याज-आय और निवल ब्याजेतर आय दोनों में आयी गिरावट के कारण 2018 में शीर्ष 100 बैंकों के माध्य आरओए में गिरावट आयी। हालांकि, आस्ति गुणवत्ता में हुए थोड़े सुधार के बल पर प्रावधानीकरण अपेक्षाओं में कमी आयी (चार्ट II.5ए और बी)।

II.20 शीर्ष 100 बैंकों की पूंजीगत स्थिति मजबूत बनी रही और 2018 में इनमें से 48 बैंकों का सीआरएआर 16 प्रतिशत से अधिक रहा। दूसरी ओर देखें तो, 12 प्रतिशत से कम

<sup>5</sup> आंकड़े फाइनेंशियल टाइम्स के बैंकर डेटाबेस से लिए गए हैं।



चार्ट II.4 : टीयर-1 पूंजी के अनुसार शीर्ष 100 बैंकों का वितरण



सीआरएआर वाले बैंकों की संख्या में गिरावट आयी। एक अन्य क्षेत्र जिसमें सुधार देखा गया, वह था लीवरेज अनुपात का – फ्रांस, जर्मनी और जापान के एक-एक बैंक को छोड़कर जो 4 प्रतिशत से नीचे रहे- शेष सभी बैंकों का लीवरेज अनुपात बेसल III नियमों के तहत निर्धारित 3 प्रतिशत से अधिक बना रहा (चार्ट II.6 ए और बी)।

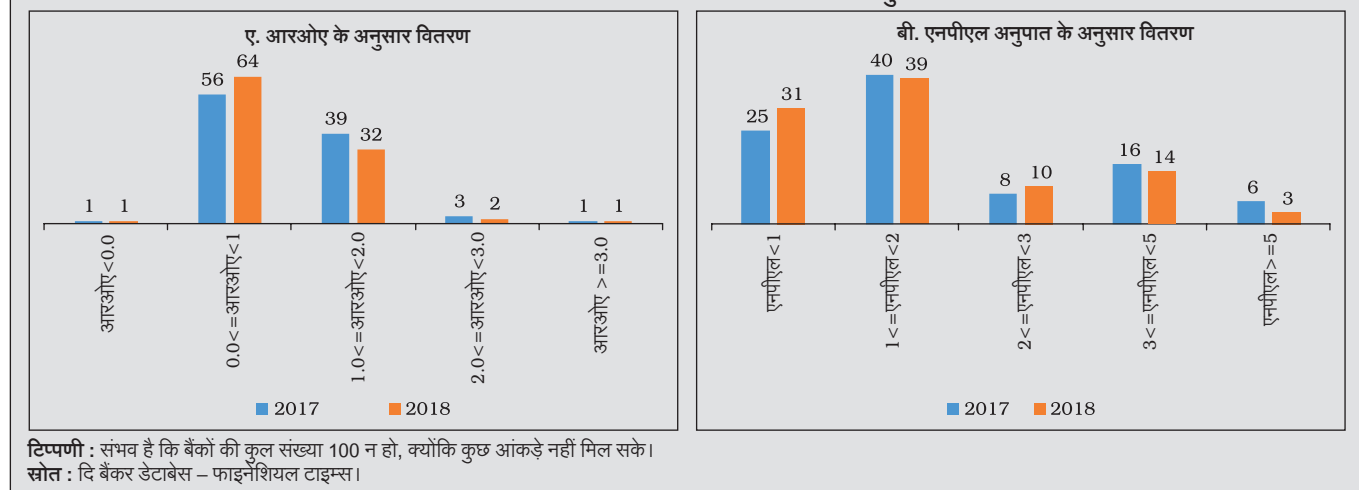
### 5. वैश्विक बैंकिंग में नीतिगत प्रगति

II.21 वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद किए गए वैश्विक विनियामकीय सुधारों को लागू किए जाने से बैंकों की पूंजी और चलनिधि बफर्स में वृद्धि हुई है। हालांकि, अनर्जक

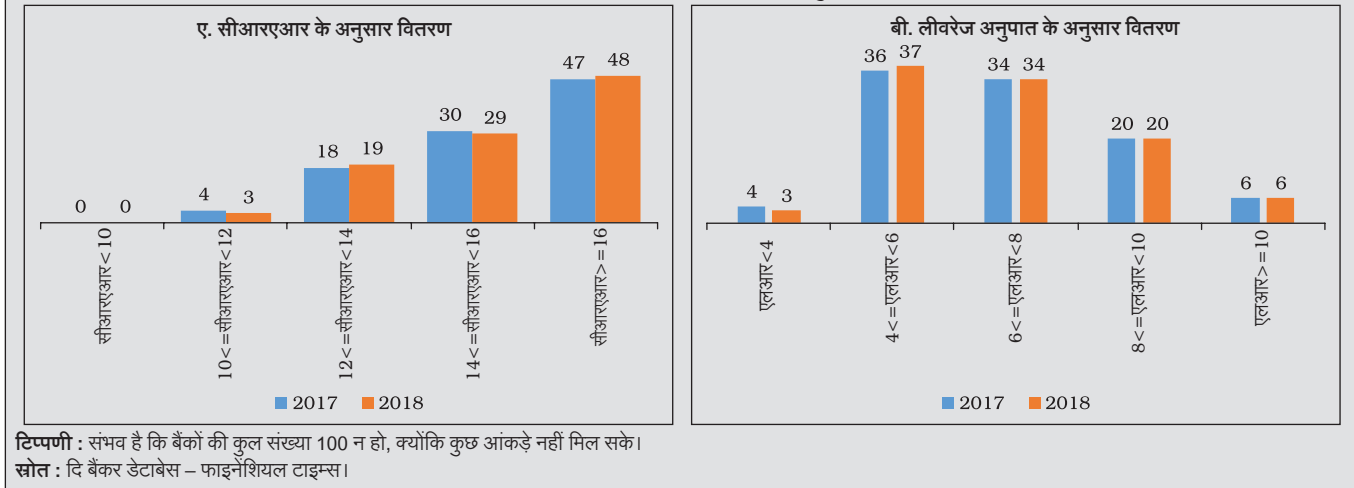
ऋणों में कमी लाने और तुलनपत्र को मजबूत करने के उनके प्रयासों को, मंद पड़ती संवृद्धि दर और घटती ब्याज दरों से झटका लगा है।

II.22 जीएफसी के बाद वैश्विक वित्तीय क्षेत्र में सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों में से प्रमुख चार इस प्रकार थे- (i) वित्तीय संस्थाओं को अधिक आघातरोधी बनाना; (ii) इतने बड़े कि डूबें ना (टीबीटीएफ) की संकल्पना को समाप्त करना; (iii) व्युत्पन्नी बाजार को अधिक सुरक्षित बनाना; और (iv) वित्तीय मध्यस्थता करने वाली ऐसी गैर-बैंकिंग संस्थाओं को बढ़ावा देना जो वित्तीय आघातों को सहन करने में अधिक सक्षम हों। इन सुधारों का कार्यान्वयन अलग-अलग चरणों में चल रहा

चार्ट II.5: शीर्ष 100 बैंकों की लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता



चार्ट II.6 : शीर्ष 100 बैंकों की बैंकिंग सुदृढ़ता



है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है, और साथ ही, वित्तीय स्थिरता के समक्ष उत्पन्न जोखिमों से निपटने के लिए नई नीतियाँ बनाता है। भ्रष्टाचार से जुड़े जोखिमों को कम करने हेतु गवर्नेंस के मानकों को सुदृढ़ बनाने और कारोबारी प्रतिनिधि के माध्यम से की जा रही बैंकिंग में आयी गिरावट का आकलन करते हुए उसका हल निकालने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

### 5.1 आघातरोधी वित्तीय संस्थाएं तैयार करना

II.23 अधिकांश एफएसबी सदस्यों ने बासेल III के जोखिम-आधारित पूंजी नियमों और लीवरेज अनुपात की प्रमुख बातों को स्वीकार कर लिया है। चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)<sup>6</sup> को लागू करने की दिशा में भी काफी प्रगति हुई है। फिर भी, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति (बीसीबीएस)<sup>7</sup> की नवीनतम प्रगति रिपोर्ट में ऐसे तीन मानकों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें अपनाने में सभी क्षेत्र पीछे रहे हैं, यथा- i) प्रतिभूतीकरण ढांचा; ii) निधियों में इक्विटी निवेश संबंधी पूंजी-अपेक्षाएं; और iii) केंद्रीकृत रूप से संसाधित न होने वाली व्युत्पन्नियों (एनसीसीडी)<sup>8</sup> के लिए मार्जिन अपेक्षाएं।

### 5.2 इतने बड़े कि डूबें ना

II.24 इतने बड़े कि डूबें ना की संकल्पना से जुड़े नीतिगत ढाँचे के विकास की दिशा में प्रगति मुख्यतः वैश्विक प्रणालीगत महत्व वाले बैंकों (जी-एसआईबी) के मामले में ही हुई है। हालांकि, प्रभावी समाधान व्यवस्था स्थापित करने और प्रणालीगत महत्व वाले बैंकों तथा गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों के लिए तैयार की गयी योजनाओं को लागू करने की दिशा में अभी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। लगभग सभी जी-एसआईबी के मूल देश में और उन प्रमुख देशों में जिनमें ये कारोबार कर रहे हैं, एक व्यापक बैंक समाधान व्यवस्था मौजूद है जो एफएसबी द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्दिष्ट प्रभावी समाधान व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के अनुरूप है। हालांकि, कई देशों में समाधान से जुड़ी शक्तियों और समाधान आयोजना संबंधी अपेक्षाएं अभी भी अधूरी हैं। सभी एई जी-एसआईबी के मूल देशों (2018 से इनकी संख्या में छह का इजाफा हो गया है) में बाहरी कुल हानि-अवशोषक क्षमता (टीएलएसी) अपेक्षाओं को अब अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि, आंतरिक टीएलएसी का कार्यान्वयन में अभी कम प्रगति हो सकी है और केवल कुछ देशों ने ही टीएलएसी

<sup>6</sup> भारत में बैंकों के लिए एनएसएफआर पर अंतिम दिशानिर्देश मई 2018 में प्रकाशित किए गए थे और बैंकों को इसे 01 अप्रैल 2020 से लागू करना है।

<sup>7</sup> बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (2018), "बासेल विनियामकीय फ्रेमवर्क को स्वीकार करने संबंधी पंद्रहवीं प्रगति रिपोर्ट", 26 अक्टूबर, <https://www.bis.org/bcbs/publ/d452.htm> पर उपलब्ध।

<sup>8</sup> प्रतिभूतीकरण फ्रेमवर्क को भारत में लागू किया जाना अभी बाकी है, जबकि एनसीसीडी के लिए मार्जिन अपेक्षाओं का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

क्रॉस-होलिडिंग्स या प्रकटीकरण संबंधी बीसीबीएस अपेक्षाओं को लागू किया है।

### 5.3 डेरिवेटिव बाजार सुरक्षित बनाना

11.25 ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव बाजार सुधार में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 23 देशों (2018 के बाद से और एक) में व्यापक रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं का कार्यान्वयन किया गया है, यद्यपि अंतरराष्ट्रीय व्यापार रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रभाव बहुत कम दिखाई दिया। केंद्रीय समाशोधन (18 देश), प्लैटफॉर्म ट्रेडिंग (13 देश) और गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव (16 देश) की मार्जिन अपेक्षाओं के फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन प्रगति पर है। भारत ने व्यापार रिपोर्टिंग और अंतरिम पूंजी अपेक्षाओं का कार्यान्वयन पूरा किया है, जब कि ओटीसी डेरिवेटिव की मार्जिन अपेक्षाओं और प्लैटफॉर्म ट्रेडिंग के कार्यान्वयन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में भारत, व्यापार रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के संबंध में जी 20 प्रतिबद्धता के अनुरूप है। ब्याज दर से संबंधित सभी ओटीसी डेरिवेटिव व्यापार- अंतर बैंक और ग्राहक व्यापार - दोनों, फोरेक्स और क्रेडिट (रूपी ब्याज दर स्वैप(आईआरएस)/वायदा दर करार(एफआरए), फोरेक्स वायदा/ फोरेक्स विकल्प, सीडीएस आदि) रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित ट्रेड रिपोजिटरी अर्थात् भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) को रिपोर्ट किए जाते हैं। भारत ने ब्याज दर, फॉरेक्स तथा क्रेडिट मार्केट के सभी गैर-व्यक्तिगत ओटीसी डेरिवेटिव व्यापार के लिए लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलआईआई) का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है।

### 5.4 आघातरोधी बैंकेतर वित्तीय मध्यस्थता को बढ़ावा देना

11.26 गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता वास्तविक आर्थिक गतिविधि को गति प्रदान करने में बैंक वित्तपोषण के लिए एक बहुमूल्य विकल्प प्रदान करता है। हालांकि, इस प्रकार

की मध्यस्थता में अंतर्निहित परिपक्वता/चलनिधि परिवर्तनों में अपरिहार्य रूप से लीवरेजिंग एवं चलनिधि असंतुलन शामिल है जो प्रणालीगत जोखिम का मूल कारण बन सकता है। अंतर्संबद्धता के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली जोखिम का एक अतिरिक्त मूल कारण है। वैश्विक तौर पर गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (एमयूएनएफआई) के निगरानी जगत की कुल वित्तीय आस्तियां 2017<sup>9</sup> में 7.0 प्रतिशत बढ़कर 184.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गईं। अन्य वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं (ओएफआई) की आस्तियां 7.6 प्रतिशत बढ़कर 116.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गईं। जीएफसी के बाद पहली बार संरचित वित्तीय माध्यमों (एसएफवी) ने अपने तुलन पत्र में विस्तार किया।

11.27 गैर-बैंक वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के एफएसबी संबंधी नीतिगत सुधार के कार्यान्वयन प्रारंभिक स्तर<sup>10</sup> पर हैं। 24 सदस्य देशों में से नौ देशों ने मनी मार्केट फंड के लिए (एमएमएफ), मूल्यांकन, चलनिधि प्रबंधन और स्थिर निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के लिए उपाय लागू नहीं किए हैं; इसी तरह, 24 देशों में से 9 देशों ने भी प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क उपाय लागू नहीं किया है। दूसरी तरफ भारत ने कार्यान्वयन संबंधी दोनों उपायों को अमल में लाया है।

### 5.5 जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण

11.28 एफएसबी ने 5 जून 2019 को जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण के संबंध में कार्यबल की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने संबंधी दूसरी स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 से जलवायु संबंधी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण में तेजी आयी है लेकिन निवेशकों के लिए अभी भी यह अपर्याप्त है, विशेष रूप इस संबंध में कि कंपनियों पर जलवायु से संबंधित मुद्दों का वित्तीय प्रभाव कितना पड़ता है।

<sup>9</sup> वित्तीय स्थिरता बोर्ड (2019), 4 फरवरी के 'गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थता 2018 पर वैश्विक निगरानी रिपोर्ट <https://www.fsb.org/2019/02/global-monitoring-report-on-non-bank-financial-intermediation-2018/> पर उपलब्ध है।

<sup>10</sup> वित्तीय स्थिरता बोर्ड (2018), 28 नवंबर के "जी 20 के वित्तीय विनियामक सुधार के कार्यान्वयन और उसके प्रभाव: चौथा वार्षिक रिपोर्ट <https://www.fsb.org/2018/11/implementation-and-effects-of-the-g20-financial-regulatory-reforms-fourth-annual-report/> पर उपलब्ध है।

11.29 इस संबंध में, आस्तियों के विविधीकरण के लिए हरित वित्त नए अवसर प्रदान करता है और अधिक टिकाऊ न्यूनतम-कार्बन वाली अर्थव्यवस्था हेतु निजी पूंजी को जुटाने के लिए वित्तीय प्रणाली की क्षमता को बढ़ाता है (बॉक्स 11.1)।

## 5.6 कदाचार जोखिम

11.30 नवंबर 2018 में, एफएसबी ने कुछ उपायों की सूची जारी की, जिसका उपयोग पर्यवेक्षी और फर्म अपनी फर्मों में कदाचार के लिए वरिष्ठ प्रबंधन की जवाबदेही को बढ़ाकर

### बॉक्स 11.1: हरित वित्त के अवसर और चुनौतियां

वित्तीय प्रणाली पर जलवायु परिवर्तन का कितना प्रभाव है इसका पता विभिन्न जोखिमों के साथ-साथ बारंबार प्राकृतिक आपदाओं से मूर्त आस्तियों को होने वाले नुकसान या क्षति; अनियमित मौसम की प्रवृत्ति के कारण खाद्य की कीमतों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न वित्तीय स्थिरता की संभावनाओं, व्यापक ऋण प्रसार और अधिक एहतियाती बचत से चलता है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और धारणीय और निम्नतम कार्बन उत्सर्जन की दिशा में कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। चूंकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपेक्षित परिवर्तन को सिर्फ लोक निधि से वित्त-पोषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए पर्यावरण के अनुकूल संधारणीय विकास के वित्त-पोषण के लिए हरित वित्त की आवश्यकता है। हरित वित्त पारिस्थिकी तंत्र बैंकिंग, सूक्ष्म-ऋण और बीमा क्षेत्रों के साथ-साथ सार्वजनिक, निजी एवं गैर-लाभकारी क्षेत्रों से वित्तीय प्रवाह बढ़ाने की कोशिश करता है।

केंद्रीय बैंक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कई नीतिगत साधनों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सभी जलवायु-संबंधित वित्तीय जोखिमों से संबंधित प्रकटीकरण अपेक्षाएं, हरित समष्टि-विवेकपूर्ण विनियमन जैसे कार्बन-गहन क्षेत्रों के लिए उच्च जोखिम-भार; अत्यधिक हरित उधार देने वाले बैंकों के लिए विभेदित पूंजी और आरक्षित अपेक्षाएं; और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए रियायती ऋण दरों के रूप में हरित ऋण नीति (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, 2017) शामिल हैं। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने औपचारिक रूप से जलवायु संबंधी जोखिम की पहचान बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख जोखिमों में से एक के रूप में की है। यह बैंकों के पूंजीगत स्थितियों पर जलवायु से संबंधित परिवर्तनों के प्रभाव और, अंततः अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति के संबंध में परिकलन करता है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना अपने मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क और वित्तीय स्थिरता आकलन में पर्यावरणीय कारकों पर विचार करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील बैंकों से अपेक्षा करता है कि वे पूंजी आवश्यकताओं की गणना करते समय पर्यावरणीय जोखिमों को भी इसमें शामिल करें। इसी तरह, वित्तपोषित परियोजना की ऊर्जा बचत क्षमता का पता लगाने के बाद, सेंट्रल बैंक ऑफ लेबनान द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को इस तरह की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए निम्नतर अपेक्षित आरक्षित निधियों के रूप में छूट दी जाती है।

जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण के मामले में अब हरित बॉण्ड, कार्बन मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स और फिनटेक आधारित हरित कोष सबसे आगे हैं। हरित बॉण्ड

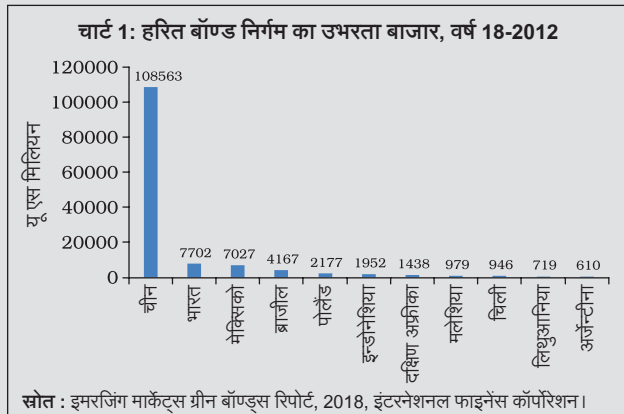
के बाजार में 50 से अधिक देशों के निर्गमकर्ता हैं, जिसमें विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं भी शामिल हैं। वर्ष 2007-2018 के दौरान, दुनिया भर में कुल 521 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हरित बॉण्ड निर्गम हुआ है, और इन निर्गमों में ईएमई के बीच भारत दूसरे स्थान पर है (क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव, 2019)। हरित ऋण एक दूसरा बहुप्रचलित लिखत है, जिसका वर्ष 2018 में 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निर्गम हुआ है और इसकी औसत परिपक्वता 15 वर्षों से अधिक रही है। 75 प्रतिशत से अधिक का बकाया हरित ऋण अक्षय ऊर्जा और बिजली उत्पादन कंपनियों को दिया गया था (अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान, 2019)।

अधिराष्ट्रीय संस्थाएं इन प्रयासों में योगदान बढ़ाती जा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पहले से ही उसे अपनी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय निगरानी में शामिल कर लिया है। सितंबर 2019 में, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन और हरित-बॉण्ड मार्केट को बढ़ाने के उद्देश्य से हरित बॉण्ड में केंद्रीय बैंक निवेशों के लिए एक ओपन-एंडेड यूएस डॉलर मूल्यवर्गित निधि प्रारम्भ किया है।

इसके फायदों के बावजूद, इससे संबंधित साहित्य से ऐसा कोई अकाट्य प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह पता चले कि पारंपरिक निधियों के मुकाबले हरित निधियां (सस्टेनेबल फंड्स) श्रेष्ठ या कमतर हैं। इस बात के भी कम साक्ष्य हैं कि हरित बॉण्ड निर्गम करने की लागत पारंपरिक बॉण्ड की लागत की तुलना में कम है (आईएमएफ, 2019)। अध्ययनों से पता चलता है कि सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानक और परिभाषा विकसित करने से हरित बॉण्ड के कीमत निर्धारण में सुधार होगा और हरित बॉण्ड बाजार के विकास में सहायक सिद्ध होगा (विश्व बैंक, 2018)।

भारतीय संदर्भ में, पेरिस समझौते के लिए किए गए प्रारंभिक अनुमान से पाता चलता है कि वर्ष 2015 और 2030 के बीच अपने जलवायु परिवर्तन कार्यों को पूरा करने के लिए कम से कम 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (2014-15 की कीमतों पर) की आवश्यकता होगी (भारत सरकार, 2015)। वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन की भारत की महत्वाकांक्षा के लिए भी बड़े पैमाने पर राशि जुटाने की आवश्यकता होगी।

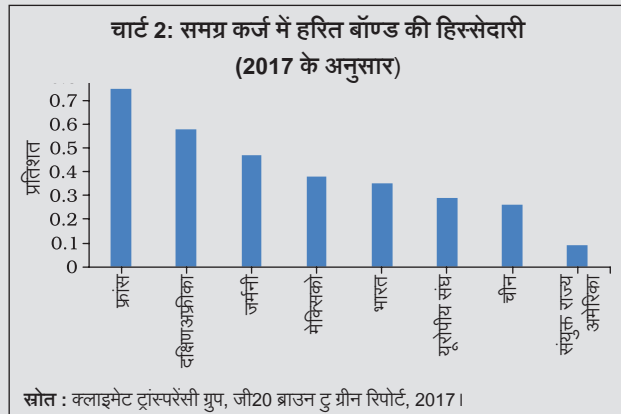
वर्ष 2007 की शुरुआत में, रिज़र्व बैंक ने गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग की आवश्यकता पर जोर दिया और वित्तीय संस्थानों से संधारणीय विकास प्रथाओं का पालन करने का आग्रह किया। भारत में बैंकों को मध्यवर्ती (जारी...)



(इक्विटी) सिद्धांतों<sup>11</sup> सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गयी पहलों के प्रति संवेदनशील बनाया गया है। वर्ष 2015 में, रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने संबंधी लक्ष्यों के भीतर सामाजिक अवसंरचना और सूक्ष्म नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को ऋण दिए जाने वाली सूची में शामिल कर लिया, जिससे हरित वित्तपोषण को और अधिक बल मिला। हरित बॉण्ड निर्गम करने के मामले में भारत अपने ईएमई समकक्षों की तुलना में अग्रणी है (चार्ट 1)।

कुल बॉण्ड मार्केट के अनुपात के अनुसार भी हरित बॉण्ड का भारतीय निर्गम अपने समकक्षों की तुलना में अच्छा ही है (चार्ट 2)। हरित बॉण्ड निर्गम करने की गति बढ़ने से वर्ष 2012-2018 के दौरान यह 7.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया जिससे सेबी को मई 2017 में भारत में हरित कर्ज प्रतिभूतियों को निर्गम और सूचीबद्ध करने के लिए प्रकटीकरण अपेक्षाओं को निर्धारित करना पड़ा।

इस प्रगति के बावजूद, हरित वित्त के विकास में कई चुनौतियां हैं, जैसे «ग्रीनवॉशिंग» अथवा पर्यावरणीय अनुपालन के झूठे दावे, हरित ऋण परिभाषाओं की बहुलता, और दीर्घावधि हरित निवेश और निवेशकों के अपेक्षाकृत अल्पकालिक ब्याज के बीच परिपक्वता बेमेल। समन्वित प्रयासों के माध्यम से जागरूकता को बढ़ावा देकर भारत में हरित वित्त पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने वाले एक सक्षम फ्रेमवर्क को स्थापित करने के लिए नीतिगत कार्रवाई जरूरी है। कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार को



बढ़ाकर, हरित निवेश शब्दावली का मानकीकरण करके, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को सुसंगत बनाकर, तथा निवेशकों और प्राप्तकर्ताओं के बीच सूचना की विषमता समाप्त करके हरित वित्त बाजार की कुछ कमियों को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।

#### संदर्भ:

क्लाइमेट बॉण्ड्स इनिशिएटिव (2019), 'ग्रीन बॉण्ड्स: द स्टेट ऑफ द मार्केट 2018'।

भारत सरकार (2015), 'भारत के अभिप्रेत राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान संतुलित एवं व्यापक हैं : पर्यावरण मंत्री,' 2 अक्टूबर, 2015, प्रेस सूचना ब्यूरो की विज्ञप्ति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, <https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=128.403> पर उपलब्ध

इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस (2019), सस्टेनेबल फाइनेंस इन फोकस - ग्रीन लोन्स — किकऑफ टाइम! 1 मई।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2019), ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट- लोअर फॉर लॉन्गर', अक्टूबर।

यूएन एन्वाइरन्मन्ट (2017), 'ऑन दि रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स इन इन्हेंसिंग ग्रीन फाइनेंस', इंकवायरी वर्किंग पेपर, 17/01, फरवरी।

वर्ल्ड बैंक (2018), दि प्राइस ऑफ ग्रीननेस: सम एविडेंस फ्रॉम ग्रीन बॉण्ड मार्केट्स', 27 सितंबर।

वित्तीय संस्थाओं के शासन ढांचे को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। इन अनुशंसाओं में क्षतिपूर्ति संबंधी प्रयासों के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए आंकड़ों के एक मूल समूह की पहचान की गयी है। उपायों को क्षतिपूर्ति परामर्शों सहित एफएसबी ने

कदाचार पर कार्रवाई – योजना के अन्य तत्वों के पूरक के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें जोखिम और प्रोत्साहन का बेहतर तालमेल है और जो वित्तीय प्रणाली में जनता के भरोसे को बहाल करने के व्यापक उपायों का एक हिस्सा है।

<sup>11</sup> मध्यवर्ती (इक्विटी) सिद्धांत एक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क है जिसे परियोजनाओं में पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम का निर्धारण करने, उसका आकलन और प्रबंधन करने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाया गया है और इसका प्राथमिक उद्देश्य जोखिम संबंधी निर्णय जिम्मेदारी के साथ लेने में सहायता प्रदान करने के लिए यथोचित सावधानी बरतने एवं निगरानी हेतु न्यूनतम मानक उपलब्ध कराना है। ये अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईएफसी) के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑन एन्वाइरन्मन्ट एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी पर आधारित हैं।

## 5.7 प्रतिनिधि बैंकिंग और धन-प्रेषण

11.31 हाल के वर्षों में जोखिम कम करने के कारण प्रतिनिधि बैंकिंग<sup>12</sup> में कमी आई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की उपलब्धता में बाधा आई है। चूंकि प्रतिनिधि बैंकिंग संबंधों में कटौती का धन-प्रेषण सेवा प्रदाताओं की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इसके कारण कुछ भुगतान प्रवाह अनौपचारिक माध्यम से हो सकता है। 2018 में, प्रतिनिधि बैंकिंग संबंधों और सक्रिय कॉरीडोर<sup>13</sup> की संख्या में क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 2.0 प्रतिशत की ओर कमी आई, जबकि 2012-2018 के दौरान क्रमशः 13 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की कमी आई थी<sup>14</sup>। जिन ईएमई में धन-प्रेषण प्रवाह, परिवारों के लिए निधि का महत्वपूर्ण स्रोत है, उनमें इससे संवृद्धि, वित्तीय समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ना संभाव्य है। बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में आरएसपी को आनेवाली समस्याओं के निराकरण के लिए मार्च 2018 में एफएसबी ने कुछ उपाय बताए और आरएसपी के लिए बैंकिंग सेवाएं खत्म होने से जुड़े कुछ अंतर्संबद्ध कारकों की पहचान की जिसमें कम लाभप्रदता, धन-शोधन निवारण व आतंकवाद के वित्तपोषण से धन प्रेषण को बड़े जोखिम वाला काम समझने की धारणा, आरएसपी का पर्यवेक्षण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन शामिल है।

## 6. उपसंहार

11.32 संवृद्धि की गति धीमी पड़ने की शुरुआत वर्ष 2018 में हो गयी और इसके साथ-साथ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में क्रेडिट वृद्धि अनुचक्रीय होने के कारण मंद हो गयी है, जिससे बैंक की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आस्ति की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार के बावजूद, दुनिया भर की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग प्रणालियों में संरचनात्मक कमजोरियां बनी हुई हैं, हालांकि पूंजी की स्थिति मजबूत हुई है। बैंकों को फिनटेक और बिगटेक फर्मों जैसे गैर-पारंपरिक खिलाड़ियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो डिजिटल नवाचार का लाभ उठा रहे हैं। वे नवाचार को बढ़ावा देने और एक समान पर्यवेक्षी और नियामक फ्रेमवर्क को लागू करने के बीच संतुलन हासिल करने में बैंकिंग नियामकों के लिए एक चुनौती भी पेश कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर, नीति निर्माता बैंकों के लिए नियामक फ्रेमवर्क को मजबूत कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों को लागू कर रहे हैं। हो सकता है कि इन नीतियों का तत्काल परिणाम नहीं दिखे, लेकिन वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता और सहनीयता को बढ़ाकर इसका असर मध्यम और दीर्घ अवधि में दिखना चाहिए।

<sup>12</sup> एफएसबी संवाददाता बैंकिंग को एक बैंक ("संवाददाता बैंक") द्वारा एक बैंक ("प्रतिवादी बैंक") द्वारा बैंकिंग सेवाओं के प्रावधान के रूप में परिभाषित करता है।

<sup>13</sup> ऐसे कंट्री पेयर्स के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें कम से कम एक लेनदेन संसाधित किया हो।

<sup>14</sup> अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, 'न्यू करस्पोंडेंट बैंकिंग डाटा - दी डिक्लाइन कंटीन्यूज़ [https://www.bis.org/cpmi/paysysinfo/corr\\_bank\\_data/corr\\_bank\\_data\\_commentary\\_1905.htm](https://www.bis.org/cpmi/paysysinfo/corr_bank_data/corr_bank_data_commentary_1905.htm) पर उपलब्ध है।